अभियान

जीवन रक्षक दवाओं की क़ीमत और उपलब्धि

कल्याणी मेनन-सेन

हर साल लगभग एक लाख भारतीय महिलाओं को स्तन कैंसर होता हैं। इनमें से करीब एक-चौथाई औरतों में HER-2+ कैंसर के लक्षण पाये जाते हैं। कैंसर का यह रूप बहुत ही तीव्रता से फैलता है, इसके दोबारा होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है और बड़ी तादात में पैंतालीस वर्ष से कम उम्र की महिलाएं इससे ग्रस्त हो रही हैं।

HER-2+ कैंसर की रोकथाम, तीव्रता को कम करने, दोबारा होने की संभावना घटाने और रोग मुक्त जीवन जीने के लिए *त्रास्तुज़ुमाब* (Trastuzumab) नाम की दवा विशेष रूप से प्रभावशाली पाई जाती है। इलाज़ के लिए इस औषधि की 12 या अधिक ख़ुराकें, हर तीन-चार हफ़्तों में नसों के ज़रिए रोगी को दी जाती हैं।

दुर्भाग्य की बात यह है कि इस दवा का लाभ बहुत कम भारतीय महिलाएं उठा पाती हैं क्योंकि इसकी क़ीमत ज़्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर है। स्विस फार्मा कम्पनी *रोषे* (Roche) द्वारा *हरसेप्टिन* (Herceptin) नाम से बेची जाने वाली यह दवा दुनिया भर में बहुत भारी क़ीमत पर बेची जा रही है। 2010 में भारत में इसकी (444 मि.ग्रा. शीशी की) क़ीमत 1.15 लाख रुपये थी। 2012 में 72000 रुपयों की कम की गई कीमत पर यह दवा *हरक्लान* (Herclon) के नाम से भारत में बेची जा रही थी।

ज़ाहिर है कि हमारे देश में इतनी मंहगी दवा अधिकांश औरतों की पहुंच के बाहर है। हमने अनेक दिल-तोड़ने वाली आपबीतियां सुनी हैं— ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें डॉक्टर इस दवा के बारे में मरीज़ों को कोई जानकारी नहीं दी है क्योंकि वे जानते हैं कि यह मरीज़ सामार्थ्य के बाहर है; मरीज़ पैसे खत्म होने के कारण अपना पूरा इलाज़ नहीं करवाते; परिवार कर्ज़ या ज़ायदाद बेचकर इस दवा को खरीदते हैं; और औरतें जीने की आस छोड़ देती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है।

नवम्बर 2012 में इस दवा को कम दाम पर मरीज़ों के लिए मुहैया कराने के लिए एक अभियान चलाया गया। *"कैम्पेन फ़ॉर अफ़ोर्डेबल त्रास्तुज़ुमाब"* नाम से शुरू की गई इस मुहिम में 200 से भी अधिक मरीज़ समूह, कैंसर सर्वाइवर्स, क़ानूनविद्, स्वास्थ्य कार्यकर्ता व महिला आंदोलन समूहों ने शिरकत की।

हमारे आंदोलन ने *रोषे* के भारतीय पेटेंट को चुनौती दी। हमने सरकार को चेताया कि किस तरह *रोषे* इस दवा में कुछ छोटे-मोटे बदलाव करके पेटेंट की अवधि को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। *रोषे* ने अन्य उत्पादकों को भी इस औषधि के सस्ते विकल्प विकसित करने के रास्ते क़ानूनी तौर पर बंद कर दिए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक विशेषज्ञों की समिति नियुक्त की जिसने इस औषधि के लिए अनिवार्य लाइसेसिंग का प्रस्ताव दिया जिससे प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके क़ीमतों में कटौती लाई जा सके सके। अगस्त 2013 में *रोषे* ने बढ़ते दबाव को देखते हुए ऐलान किया कि वह *त्रास्तुज़ुमाब* से जुड़ा अपना पेटेंट अधिकार छोड़ रही है जिससे इस दवा के अन्य कम क़ीमती उत्पादन विकसित किए जा सकें।

इसके ठीक तीन महीनों के बाद भारतीय बायो-फार्मा कम्पनी 'बायोकॉन' ने घोषणा की कि उसे *त्रास्तुज़ुमाब* की तरह की दवा को बिक्री का अधिकार हासिल हो गया है। 'बायोकॉन' ने इस दवा को यूएस की कम्पनी 'मायलन लेबोरेट्रीज़' के लिए विकसित किया था। 'बायोकॉन' की किरण मजूमदार शॉ ने यह भी आश्वासन दिया कि यह दवा 'उचित' क़ीमतों पर भारत में उपलब्ध कराई जाएगी।

जनवरी 2014 में जब बायोकॉन ने *त्रास्तुज़ुमाब* को *कैनमैब* (Canmab) ब्रांड के तहत बाज़ार में उतारा तो 150 मि.ग्रा. शीशी की क़ीमत 19,500 रुपये और 440 मि.ग्रा. शीशी का मूल्य 57,500 रुपये रखा गया। हालांकि

कैनमैब की छोटी शीशी रोगियों को फ़ायदा पहुंचा सकती है पर अफ़सोस यह है कि कैंसर के मरीज़ों के लिए ज़रूरी 440 मि.ग्रा. की शीशी का मूल्य व *हरसेप्टिन/हरक्लॉन* की मौजूदा क़ीमत में कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं है।

अभियान ने अब 'बायोकॉन' और उसके अमरीकी पार्टनर 'मायलन' से अपील की है कि *'कैनमैब'* की क़ीमत 1000/- (150 मि.ग्रा.) और 5000/- (440 मि.ग्रा.) रखी जाये जिससे HER-2+ ग्रस्त भारतीय महिलाओं को स्वस्थ और रोगमुक्त जीवन जीने का मौका मिल सके। साथ ही क़ीमत को कम करने से दूसरे विकासशील देशों में रहने वाली उन करोड़ों महिलाओं को भी राहत मिल सकेगी जो स्तन कैंसर से जूझ रही हैं।

पर *त्रास्तुज़ुमाब* ही केवल एक ऐसी कैंसर की दवा नहीं है जो ज़रूरतमंदों की पहुंच से बाहर है। कुछ अन्य दवाएं भी हैं— जैसे ल्यूकीमिया-खून के कैंसर में उपयोगी दवा *दसातिनिब* (Dasatinib) जिसकी एक महीने की खुराक की क़ीमत एक लाख रुपये है। इसे बनाने वाली कम्पनी ब्रिसटल-मायर्स-स्क्विब ने इसका विकल्प बनाने वाले उन भारतीय उत्पादाकों के ख़िलाफ़ आदेश हासिल कर लिया है जो इसे मूल क़ीमत की दसवीं क़ीमत इसका विकास करने की क्षमता रखते हैं।

सच्चाई तो यह है कि सामाजिक ज़िम्मेदारी के तहत फार्मा कम्पनी द्वारा चालए 'उपलब्धता कार्यक्रम' या 'स्वेच्छा से कम की गई क़ीमतों' से दवाओं के मूल्य बहुत अधिक कम नहीं किए जा सकते बल्कि बाज़ार में दूसरे उत्पादकों की मौजूदगी से होने वाली खुली प्रतिस्पर्धा इसमें अधिक कारगर साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम्पनियां वैश्विक बाज़ार पर नज़र रखकर ही अपनी क़ीमत सबंधी नीतियां तय करती हैं— भारत में क़ीमतें कम होने का प्रभाव दूसरे देशों के बाज़ार पर भी पड़ता है। *रोशे* ने भी चौदह सालों तक मुनाफ़ा कमाने के बाद ही इस दवा की क़ीमत कम की थी। इस रणनीति के तहत अपने निवेश में करोड़ों का इज़ाफ़ा करने के बाद ही यह क़दम उठाया गया था— हालांकि इसके कारण विकासशील देशों में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गवां कर इस मुनाफ़े में वृद्धि की।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष सात लाख भारतीय कैंसर से मरते हैं। करीब दस लाख लोगों को हर वर्ष कोई न कोई बीमारी से जूझना पड़ रहा है। इसमें HER-2+ स्तन कैंसर के 25000 केस भी शामिल हैं।

कैंसर औषधियों की लड़खड़ाती क़ीमतों का मानवीय मूल्य आंके तो हम जानेंगे कि यह कितनी सर्वग्राही रही है; फिर चाहे यह अनुमान मरने वालों की संख्या, इंसानों की पीड़ा या उनके परिवारों द्वारा झेले जाने वाली यातना के आधार पर लगाया गया हो। इन परिस्थितियों में दवाओं की क़ीमत को नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से उसकी उपलब्धि को लेकर सरकार की बेरुखी हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है।

हम एक बार फिर भारत सरकार से मांग करते हैं कि वे इस सच को पहचानें कि *त्रास्तुज़ुमाब* जैसी कैंसर विरोधी, जीवन रक्षक दवाओं की ऊंची क़ीमतें इस मूक महामारी को रोकने की राह में रुकावट पैदा कर रही हैं। हमारी गुज़ारिश है कि सरकार इन दवाओं के मूल्य को नियंत्रित करने की दिशा में ठोस क़दम उठाए।

हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि:

- अपनी शक्ति का उपयोग करके पेटेंट संबंधी रुकावटों को हटाने के लिए सशक्त अनिवार्य लाइसेंसिग जैसे क़दम उठाएं विशेषकर जब सवाल मंहगी कैंसर की दवाओं के सस्ते विकल्प विकसित करने का हो।
- भारतीय बाज़ार में कैंसर औषधियों की क़ीमतों पर निगरानी व नियंत्रण रखें और सभी पेटेंट की गई कैंसर औषधियों को औषधि मूल्य निर्धारण प्रणाली की परिधि में लाने का आदेश पारित करें।
- भारत के सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से कैंसर की औषधि मुहैया कराएं।
- मरीज़ समूहों, स्वास्थ्य अधिकार समूहों, नागरिक समाज संगठनों के साथ विचार-विमर्श करके कैंसर की दवाओं के मूल्य को कम करने और उन तक पहुंच बढ़ाने के लिए ठोस अगुवाई करें।

कल्याणी मेनन सेन *नारीवादी शोधकर्त्ता व लेखिका हैं।*